



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99]  
No. 99]नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 7, 2005/फाल्गुन 16, 1926  
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 7, 2005/PHALGUNA 16, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2005

सं. 28/2005—सीमाशुल्क

सा.का.नि. 160(अ)।—अभिहित प्राधिकारी, चूर्णपीय संघ, सिंगापुर और जोर्जिया (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) में भूलतः उद्गमित या वहां से निर्यातित, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के टैरिफ मद 2936 21 00 के अंतर्गत आने वाले, विटामिन ए पार्मीटेट के आवात के मामले में, अपने अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना सं. 65/1/2001-डीजीएडी, तारीख 23 जनवरी, 2003 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 23 जनवरी, 2003 में प्रकाशित हुई, उसके द्वारा संबद्ध देशों में उद्गमित या वहां से निर्यातित विटामिन ए पार्मीटेट के सभी आवातों पर निश्चयात्मक प्रतिपाठन शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी;

और अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने, सा.का.नि. 205 (अ), तारीख 7 मार्च, 2003 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (i), तारीख 7 मार्च, 2003 में प्रकाशित, भारत सरकार के तदेन वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 40/2003-सीमाशुल्क, तारीख 7 मार्च, 2003 द्वारा विटामिन ए पार्मीटेट पर निश्चयात्मक प्रतिपाठन शुल्क अधिरोपित किया था;

और अभिहित प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 24 जनवरी, 2005 में प्रकाशित पुनर्विलोकनाधीन अन्तिम निष्कर्षों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि—

- (क) संबद्ध देशों में भूलतः उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित विटामिन ए पार्मीटेट से भारत में पाठन जारी है;
- (ख) परन्तु विटामिन ए पार्मीटेट के आवातों से भरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं पहुंची है;
- (ग) संबद्ध देश से विटामिन ए पार्मीटेट के आवातों पर भौजूदा याटनरोधी शुल्क समाप्त करने से भरेलू उद्योग को क्षति रहने अथवा इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 7क की उपधारा (5) के साथ पठित उपधारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ (पार्टित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाठित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 40/2003-सीमाशुल्क, तारीख 7 मार्च, 2003 को जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 205(अ) तारीख 7 मार्च, 2003 को प्रकाशित की गई थी, उसके विषयपूर्ण से पूर्व की गई या किए जाने से लोप की गई आवातों की वापत के सिवाय, विलिप्पित करती है।

[पा. सं. 354/80/2002-टी.आर.यू.]

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2005

No. 28/2005-CUSTOMS

**G.S.R. 160(E).**—Whereas in the matter of import of Vitamin A Palmitate, falling under tariff item 2936 21 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, European Union, Singapore and Georgia, the designated authority, *vide* its final findings notification No. 65/1/2001-DGAD dated the 23rd January, 2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 23rd January, 2003, had recommended the imposition of definitive anti-dumping duty on all imports of the said Vitamin A Palmitate, originating, in or exported from European Union and Georgia;

And whereas on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed an anti-dumping duty on Vitamin A Palmitate *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 40/2003-Customs, dated the 7th March, 2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 205(E), dated the 7th March, 2003;

Whereas the designated authority *vide* its final findings in review, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 24th January, 2005, has come to the conclusion that—

- (a) dumping continues from the European Union, Singapore and Georgia and is likely to continue;
- (b) the domestic industry does not suffer any material injury on account of these dumped imports as the import prices and the sales realizations of the domestic industry are above the non-injurious price so determined;
- (c) injury to the domestic industry is not likely to recur if the duties are revoked;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1), read with Sub-section (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act and Rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 40/2003-Customs, dated the 7th March, 2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 205(E), dated the 7th March, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 354/80/2002-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.